VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(06 April 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- भारतीय रिज़र्व बैंक की नवीनतम मौद्रिक नीति वक्तव्य
- नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (NATO) के 75 वर्ष पूरे
- चीन 'AI-जनित दुष्प्रचार' द्वारा भारत में लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है: माइक्रोसॉफ्ट
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारतीय रिज़र्व बैंक की नवीनतम मौद्रिक नीति वक्तव्य:

परिचय:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 अप्रैल को वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति की घोषणा की।
- RBI ने अपने प्रमुख नीतिगत दर - रेपो दर (*वह दर जिस पर RBI बैंकों को उनकी अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार देता है*) को लगातार सातवीं बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया।

- RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है।
- वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए CPI मुद्रास्फीति को 4.5% अनुमानित किया है।

RBI ने अपनी प्रमुख नीतिगत दर अपरिवर्तित क्यों रखी है?

- उल्लेखनीय है कि RBI ने आखिरी बार मई 2020 में रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर 4 प्रतिशत कर दी थी, जबकि देश भर में कोविड महामारी फैली

थी, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिससे मांग में मंदी, उत्पादन में कटौती और नौकरी छूट गई थी।

- देखा जाये तो विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ चुनौतियों के बावजूद समग्र आर्थिक दृष्टिकोण उत्साहित बना हुआ है। हालांकि मुद्रास्फीति में व्यापक आधार पर नरमी आई है, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी चिंता का विषय है।
- RBI गवर्नर ने आगे कहा कि "दो साल पहले, लगभग इसी समय, जब अप्रैल 2022 में CPI मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, उस समय मुद्रास्फीति कमरे में हाथी थी। हाथी अब घूमने निकल गया है और जंगल की ओर लौटता दिख रहा है। हम चाहेंगे कि हाथी जंगल में लौट जाए और टिकाऊ आधार पर वहीं रहे"।
- दूसरे शब्दों में, उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में, यह आवश्यक है कि CPI मुद्रास्फीति स्थिर रहे और टिकाऊ आधार पर लक्ष्य के अनुरूप रहे। गवर्नर ने रेखांकित किया कि हालांकि मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है, लेकिन यह 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।
- RBI ने संकेत दिया है कि जुलाई 2024 तक चलने वाले अनुकूल आधार प्रभाव के कारण आने वाले महीनों में आधारभूत मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। इस वर्ष

सामान्य मानसून की उम्मीद के साथ-साथ बाजार में रबी फसल के आगमन से भी खाद्य कीमतों पर दबाव कम हो जाएगा।

GDP के विकास दर का अनुमान:

- RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में GDP वृद्धि का अनुमान 7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
- अर्थव्यवस्था के समक्ष, भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और भू-आर्थिक विखंडन से प्रतिकूल परिस्थितियां, जोखिम पैदा कर रही हैं।
- जहां तक घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती की बात है, यह एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र द्वारा समर्थित है जो दोहरे अंकों में बढ़ रहा है। इसके अलावा, निवेश स्थिर गति से बढ़ रहा है जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर:

- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 29 मार्च, 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इससे पहले अक्टूबर 2021 में 645 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था।

- लेकिन RBI द्वारा वैश्विक बाजार के दबाव के बीच रुपये के मूल्य की रक्षा के लिए इनमें से कुछ भंडार को मार्केट में लाया गया था, जिस के बाद इसमें गिरावट आई थी। RBI की नीतिगत घोषणा के बाद भारतीय रुपया मजबूत हुआ है और फिलहाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.39 पर कारोबार कर रहा है।
- उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्राओं और सोने और चांदी जैसी अन्य आरक्षित संपत्तियां हैं जो किसी देश के केंद्रीय बैंक या किसी अन्य मौद्रिक प्राधिकरण के पास होती हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से देश के भुगतान को संतुलित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मुद्रा विनिमय दर स्थिर बनी रहे।

मौद्रिक नीति समिति के गैर-नीतिगत फैसले:

- IFSC में सॉवरेन ग्रीन बांड की ट्रेडिंग के लिए योजना की घोषणा की जाएगी
- GSec बाजार में भागीदारी के लिए RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजना (RDS) तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल ऐप की शुरुआत
- UPI सक्षम नकद जमा सुविधा की व्यवस्था करना
- तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन के माध्यम से प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPI) के लिए UPI एक्सेस
- गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के माध्यम से CBDC का वितरण

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (NATO) के 75 वर्ष पूरे:

परिचय:

- 4 अप्रैल को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (NATO) के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा, "नाटो पहले से कहीं अधिक बड़ा, मजबूत और अधिक एकजुट है"।
- 32 सदस्य-राज्यों के साथ इसके विस्तार से यह एक संबंध में सच हो सकता है। हालांकि, नाटो को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

- उल्लेखनीय है कि रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने और जारी संघर्ष के पीछे नाटो का विस्तार एक प्रमुख कारक माना जाता है। नाटो के वर्षगांठ पर रूस के प्रवक्ता ने नाटो के साथ रूस के संबंधों के बारे में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि नाटो के साथ संबंध अब "सीधे टकराव के स्तर पर आ गए हैं"।

NATO (नाटो) की स्थापना क्यों की गई थी?

- नाटो एक पश्चिमी सुरक्षा गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को हुई थी, जिसके 12 संस्थापक सदस्य थे - बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड,

इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

- इन देशों ने 'वाशिंगटन संधि' पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 से शक्ति मिलती है, "जो स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत या सामूहिक रक्षा के अंतर्निहित अधिकार की पुष्टि करता है"।
- NATO गठबंधन के मूल में "सामूहिक सुरक्षा" की अवधारणा है - किसी भी सदस्य पर हमला उन सभी पर हमले के रूप में देखा जाता है और सामूहिक कार्रवाई की मांग करता है।
- उल्लेखनीय है कि 1949 में तत्कालीन USSR और अमेरिका के बीच वैचारिक और आर्थिक श्रेष्ठता को लेकर शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता के बीच इसे आवश्यक समझा गया था।

सामूहिक सुरक्षा पर वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 का मामला:

- सामूहिक सुरक्षा पर वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 को "उस जोखिम का मुकाबला करने के लिए जोड़ा गया था कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप पर अपने नियंत्रण को यूरोपीय महाद्वीप के अन्य हिस्सों तक बढ़ाना चाहेगा"।
- USSR ने भी अपने सहयोगियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा और 1955 में, समाजवादी देशों के गठबंधन के रूप में 'वारसॉ पैक्ट' का गठन किया गया।

- उल्लेखनीय है कि वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के तहत नाटो के सभी सदस्यों को मिलकर सीधे सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कार्रवाई का पैमाना प्रत्येक सदस्य देश पर निर्भर करता है "जैसा वह आवश्यक समझे"।
- अब तक इस अनुच्छेद को एकमात्र बार 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले के बाद लागू किया गया था। जब नाटो सेनाओं को अफगानिस्तान भेजा गया और वहां वे लगभग 20 वर्षों तक तैनात रहीं।

आज नाटो के सदस्य कौन हैं?

- मूल 12 सदस्य देशों के अलावा, सदस्यों में ग्रीस और तुर्की (1952) शामिल हैं; पश्चिम जर्मनी (1955; बाद में जर्मनी के रूप में); स्पेन (1982); चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड (1999); बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया (2004); अल्बानिया और क्रोएशिया (2009); मोंटेनेग्रो (2017); उत्तर मैसेडोनिया (2020); फ़िनलैंड (2023); और स्वीडन (2024)।
- 1991 में सोवियत संघ के विघटन के कुछ वर्षों बाद, 1999 में नए प्रवेशकों की लहर चल पड़ी थी।

नाटो को आज किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- जब नाटो सदस्य 2019 में स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए, तो सदस्यों के बीच स्पष्ट तनाव था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तर्क दिया कि देशों को अपना सैन्य खर्च बढ़ाने की जरूरत है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में, रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद नाटो सदस्यों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने का वादा किया था। हालांकि, केवल कुछ ही देश इस सीमा को पूरा कर पाए।
- हालाँकि ऐसा लगता है कि यूक्रेन-रूस युद्ध ने नाटो को एकजुट होने के लिए एक नया फोकस क्षेत्र दिया है, लेकिन युद्ध के लिए धन देना फिर से सदस्यों के बीच असहमति का एक स्रोत बन गया है।
- इस बीच, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प अब राष्ट्रपति के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। अपने चुनाव अभियान में उन्होंने कहा है कि अमेरिका उन देशों की रक्षा नहीं करेगा जो 2 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं, जिससे संभावित ट्रम्प प्रशासन के तहत गठबंधन के भविष्य के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

साभार: द इंडियन एक्सप्रेस

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

चीन 'AI-जनित दुष्प्रचार' द्वारा भारत में लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है: माइक्रोसॉफ्ट

चर्चा में क्यों है?

- माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 5 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत में आगामी लोकसभा चुनावों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में होने वाले अन्य चुनावों को बाधित करने के लिए AI के माध्यम से उत्पन्न सामग्री का उपयोग करने वाला है।

- माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विश्लेषण में कहा है कि "जैसे-जैसे भारत, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चीनी साइबर और प्रभाव संचालक, कुछ हद तक उत्तर कोरियाई साइबर एजेंटों के साथ, इन चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

परिष्कृत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस संचालन:

- माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस के एक विस्तृत विश्लेषण में, यह पता चला है कि चीनी साइबर कार्यकर्ता और इन्फ्लुएंसर सक्रिय रूप से विभिन्न क्षेत्रों में जासूसी और इन्फ्लुएंस संचालन में लगे हुए हैं।
- चीनी इन्फ्लुएंस अभियानों ने अपनी तकनीकों को परिष्कृत किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर विभाजन पैदा करने और ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दरार को बढ़ाने के लिए एआई-जनित सामग्री का उपयोग किया है।
- AI-जनरेटड मीम्स और ऑडियो सामग्री का लाभ उठाते हुए इन अभियानों ने अमेरिका में घरेलू मुद्दों और एशिया में भू-राजनीतिक तनाव दोनों को लक्षित किया है।

अन्य देशों में चुनाव को प्रभावित करने की चीनी सरकार की योजना:

- माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्ट में कहा कि चीन ने पहले ही जनवरी में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में AI-जनित दुष्प्रचार अभियान का प्रयास किया था।
- कंपनी ने कहा, यह पहली बार था जब उसने किसी राज्य समर्थित इकाई को विदेशी चुनाव को प्रभावित करने के लिए एआई-निर्मित सामग्री का उपयोग करते देखा था।

- लेकिन, माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी कि चीन के लक्ष्य इस साल ताइवान से कहीं आगे तक जा सकते हैं।
- कंपनी ने कहा कि उसने "जून 2023 से चीन और उत्तर कोरिया के कई उल्लेखनीय साइबर और इन्फ्लुएन्स रुझान देखे हैं जो न केवल परिचित लक्ष्यों को दोगुना टार्गेटेड हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक परिष्कृत इंफ्लुएंस तकनीकों का उपयोग करने का भी प्रयास कर रहे हैं"।

चीनी साइबर कार्यकर्ताओं के लक्ष्य:

- माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया कि चीनी साइबर कार्यकर्ताओं ने पिछले सात महीनों में मोटे तौर पर तीन लक्षित क्षेत्रों का चयन किया: एक समूह ने दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर संस्थाओं को लक्षित किया, दूसरे समूह ने दक्षिण चीन समुद्री क्षेत्र में क्षेत्रीय विरोधियों के खिलाफ साइबर हमलों की एक श्रृंखला जारी रखी और तीसरे समूह ने अमेरिकी रक्षा औद्योगिक आधार से समझौता किया।
- माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि फ्लैक्स टाइफून नामक एक चीनी साइबर कार्यकर्ता ने यूएस-फिलीपींस सैन्य अभ्यास से संबंधित संस्थाओं को भी निशाना बनाया और 2023 की शुरुआत और सर्दियों में फिलीपींस, हांगकांग, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में इकाइयों को लक्षित किया है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQ:

Q.1. हाल ही में RBI ने अपने प्रमुख नीति दर - रेपो दर को लगातार सातवीं बार अपरिवर्तित रखा है। रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. रेपो दर वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उनकी अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार देता है।
2. रेपो दर वह दर है जिस पर बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम राशि जमा के रूप में रखनी होती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a)

Q.2. हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने निम्नलिखित कौन-सा/से गैर नीतिगत फैसला किया है/हैं?

(a) IFSC में सॉवरेन ग्रीन बांड की ट्रेडिंग के लिए योजना की घोषणा

(b) गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के माध्यम से CBDC का वितरण

(c) UPI सक्षम नकद जमा सुविधा की व्यवस्था करना

(d) उपर्युक्त सभी

Ans. (d)

Q.3. हाल ही में चर्चा में रहे 'नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (NATO)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. NATO गठबंधन के मूल में "सामूहिक सुरक्षा" की अवधारणा है।
2. "सामूहिक सुरक्षा" की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 से शक्ति मिलती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)

Q.4. हाल ही में चर्चा में रहा 'NATO' को आज किस/किन चुनौती/चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

(a) सदस्य देशों में सैन्य खर्च को लेकर मतभेद बना हुआ है।

(b) USSR के विघटन के बाद इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि लगभग रुक गयी है।

(c) यूक्रेन-रूस युद्ध ने नाटो सदस्यों के बीच मतभेद को बढ़ा दिया है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans. (a)

Q.5. माइक्रोसॉफ्ट की 'भारत में लोकसभा चुनावों में चीनी AI-जनित दुष्प्रचार' को लेकर रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्ट में कहा कि चीन द्वारा पहली बार किसी राज्य समर्थित इकाई को विदेशी चुनाव को प्रभावित करने के लिए एआई-निर्मित सामग्री का उपयोग किया जायेगा।
2. रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पहले ही जनवरी में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में AI-जनित दुष्प्रचार अभियान का प्रयास किया था।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b)